

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 373 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SUMIT SAINI

...APPLICANT

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS.

RESPONDENTS

INDEX

S`L. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply by Applicant on uploaded order copy dated 18-04-2024 on Plyboard Industries' matter. Next hearing date is 21-08-2024	1 – 4
2.	Annexure -1 Copy of Relocation Policy.	5 – 12

Filed by:

Filed on: 16.08.2024

Applicant,



Sumit Saini

S/o Shri Rajinder saini, Kishan Pura Damla

Yamunanagar-135001, Haryana

Ph. +919034103390

Email: sainisumit96@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.373 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SUMIT SAINI

...APPLICANT

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS.

RESPONDENTS

REPLY BY APPLICANT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

To,

Honorable judge and Expert Member,
National Green Tribunal,
Principle Bench, New Delhi

विषय : Reply by Applicant against Plyboard Industries matter. Next hearing date in the matter is 21 Aug 2024.

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुमित सैनी गांव निवासी दामला, जिला यमुनानगर, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में case No. 373/2022 याचिका दायर की गई है। केस की अगली सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा 21 August 2024 को निर्धारित की गई है।

मैं माननीय कोर्ट को बताना चाहता हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 21 मुझे और आमजन को जीवन जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ही सम्मान सहित स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार देता है। जिसका पूर्ण रूप से प्रतिवादियों द्वारा उलंघन किया जा रहा है और इसमें सम्बन्धित विभाग, शासन व प्रशासन खुद भी इसका उलंघन कर रहे हैं व इसे लागू कराने में असमर्थ हैं।

इन सब मामलों में Haryana state pollution control board, Haryana government के साथ साथ सभी प्रतिवादी (Respondent) भी सम्मान रूप से जिम्मेदार है। और आरोपित पक्ष स्वयं मामले की जाँच कर रहा है। और हमे कही भी हो चुकी जाँच का सम्मान रूप से भागीदार नहीं बनाया गया है तो न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

मैं पुनः कोर्ट के समक्ष Plyboard Industries matter, जिसकी अगली सुनवाई 21-08-2024 को है।, इस विषय के सन्दर्भ में अपनी निम्न लिखित दलीले, तथ्य व सुबूत पेश कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि इनका संज्ञान लेते हुए हमें माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय दिया जाए।

Case No. Plyboard Industries

1. जैसे कि मैं पहले भी कोर्ट को सूचित कर चुका हूँ कि यह सब फैक्ट्रियां गांव के residential area में कैसे चल रही हैं। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इनको हटाने के लिए policy भी लाई गई थी परन्तु प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मैं इस document का पेज yellow mark annexure-1 करके attached कर रहा हूँ।
2. अभी तक किसी भी पार्टी को नोटिस व आरोपित पक्ष नहीं बनाया गया।
3. इसके साथ ही HSPCB Report में दिखाया गया है कि सभी pollution control equipment installed हैं। जबकि कही नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जबकि Department ने अपनी रिपोर्टों में economiser/air preheater को भी pollution control equipment में दिखाया है। जो इस categories में आता ही नहीं है।
4. अभी नए Rules में कई तरह की कंपनियों को लगने के लिए pm level 25 mg/nm³ तक recommend किया गया है परन्तु plyboard industry के लिए अभी तक 1200 mg/nm³ से उपर है। जो कि समय के साथ कम होना चाहिए था। क्योंकि 15-20 साल पहले गिनी चुनी फैक्ट्रियां होती थी परन्तु अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस प्रकार emissions भी ज्यादा होगा। जिसके लिए मानकों में सुधार होना चाहिए था। अब तो technology भी उपलब्ध है परन्तु सुधार की कोई भी recommendation board द्वारा नहीं की गई है। Cyclone सिर्फ Particulate matter को रोक सकता है वो भी अगर new technology से high efficient design हो। जबकि हमारे गाँव की छतों पर काली राख, व धुआँ बना रहता है। इतनी संख्या में फैक्ट्रियों से sulphur dioxide and nitrogen dioxide को control करने के लिए कुछ भी प्रवाधान नहीं है। जिसको साफ करने के लिए scrubber होना चाहिए। फिर इस recirculate पानी को भी साफ करने के लिए ETP plant होना चाहिए।
5. HSPCB की report में लिखा है कि इन फैक्ट्रियों में domestic effluent के अलावा कुछ

- भी पानी waste नहीं है। जिसके लिए septic tank है। जबकि सभी फैक्ट्रियां ply को चिपकाने के लिए glue तैयार करती हैं जिसमें urea और formaldehyde chemical का इस्तेमाल होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ ये सब कहा जाता है। और इससे हवा और पानी दोनों विषैले हो रहे हैं ये आँखों व skin की बीमारियाँ फैलाता है।
6. हमारे सिर्फ एक गाँव में 24 plyboard फैक्ट्रियां चल रही हैं और जिले में 700+ हैं। जिनमें हजारों टन लकड़ी boiler में जलाई जा रही हैं। जिससे पूरा इलाका विषैली गैसों, काले धुएँ व राख से ग्रसित रहता है जिससे गंभीर बीमारियाँ भी होती हैं। और बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित होता है। इतनी बड़ी स्तर की environment की अवहेलना तो पूरे देश में कहीं और नहीं होगी और HSPCB की submitted report के अनुसार सब सही है। जो जांच department ने की थी और कोर्ट में जमा करवाई थी वह कहीं से भी complete व सही नहीं लगती है मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि जांच centre pollution control board द्वारा कराई जाए। और साथ ही इसमें याचिकाकर्ता को भी सहभागी बनाया जाए। जिसमें CPCB की टीम के साथ याचिकाकर्ता भी sample ले सके और खुद अलग से जांच करा सके। अगर कोई online analysis site पर ही होना है तो याचिकाकर्ता उसकी पुष्टी के लिए site पर ही मौजूद रहे। ताकि पूर्ण रूप से सही मायनों में व संदेह रहित जांच हो सके।
7. इसके अलावा सभी कम्पनियाँ chemical (गुल्लू, यूरिया, formaldehyde) युक्त बची हुई लकड़ी को जलाते हैं तो विषैला काला धुआँ उत्पन्न होता है। यह formaldehyde chemical आँखों व skin को नुकसान पहुँचाने के अलावा कैंसर कारक भी है साथ ही wood waste भी जलाते हैं जबकि Delhi व NCR में ऐसा करना बैन है। फिर हम क्या उन लोगों से भिन्न हैं। Supreme court ने भी अपने एक order, Jan 2024 में माना था कि जो treat Delhi NCR के लोगों के लिए होगा वही बाकी देश के लिए भी होगा। इस order का news विवरण मैं नीचे दे रहा हूँ। The Supreme Court on Jan Thursday 2024 berated the National Green Tribunal (NGT) for suggesting that trucks heading to an Inland Container Depot (ICD) at Delhi's Tughlakabad be diverted to ICDs outside the National Capital Region (NCR) [Container Corporation of India Ltd vs Ajay Khera and ors]. A bench of Justices Abhay S Oka and Pankaj Mithal said that the right to clean air is not the entitlement of people living in Delhi alone and a suggestion to divert trucks to other ICDs was unjustified and unwarranted.
- "The NGT has inter alia observed that there is an option to restrict the entry of diesel vehicles in the said ICDs at Tughlakabad by diverting these vehicles to the ICDs at Dadri, Rewari, Ballabgarh, Khatuawas or any other ICD around Delhi so as to control the

pollution in Delhi NCR, as if only the people living in Delhi NCR alone are entitled to pollution free atmosphere and not those living in other parts of the country. Such an observation by the NGT is in complete ignorance of the fact that citizens living in other parts of the country other than Delhi NCR also have a fundamental right to a pollution free environment as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India. Such a fundamental right is equally enforceable by all and is not confined to the people of Delhi NCR," the Supreme Court stated.

इसलिए मैं माननीय न्यायालय NGT से अपील करता हूँ कि उपरोक्त बातों व तथ्यों का संज्ञान लेते हुए व इतने जनमानस के स्वास्थ्य व बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाए । ताकि हम गांव वालों का जान माल का नुकसान रुक सके।

मैं माननीय न्यायालय से Ditch drain के केश को भी अलग से इन बाकि सभी केशों की तरह open करने की request करता हूँ । ये कही छूट गया है । ये भी मेरी शिकायत का हिस्सा था। इसका फैसला Court 2018 से कर रहा है और direction दे कर Case 2019 में dismiss कर दिया गया था । परन्तु मेरी नई याचिका 2022 में आने के बाद यह पुनः सुनवाई में आया। परन्तु यह समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है । प्रशासन बस बाते बना रहा है। और Pollution और गंदगी वैसे ही आज है। जैसे 6 साल पहले थे। और ये यमुना को भी बुरी तरह से गंदा कर रहा है । ये 35-40 km लम्बी ditch drain जहां से भी जा रही है Pollution और बीमारियाँ फैला रही है। जिले की बड़ी बड़ी industry का waste इसका कारण है ।

धन्यवाद ।

याचिकाकर्ता

सुमित सैनी

शहरी स्थानीय
निकाय निदेशालय
हरियाणा



DIRECTORATE OF URBAN
LOCAL BODIES
HARYANA

वे सं. 11-14, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा
Bay No. 11-14, Sector 4, Panchkula, Haryana

Tel.: +91 172 2570020 ; Fax: +91 172 2570021
website: www.ulbhry.gov.in ; email: dulbhry@hry.nic.in

To

The Principal Secretary to Govt. Haryana,
Industries Department

The Principal Secretary to Govt. Haryana,
Environment Department

The Director General,
Town and Country Planning Department, Haryana

The Chief Administrator,
Haryana Urban Development Authority

The Managing Director,
HSIIDC, Panchkula

The Commissioner,
Municipal Corporation, Gurgaon

The Commissioner,
Municipal Corporation, Faridabad

Memo no. DULB/CTP/TP/A2/2016/ 5534-40
Dated: 04/8/16

Subject: Relocation Policy for shifting of Industrial Units operating from residential areas (CWP no. 11226 of 2013 (O&M) titled as Progress Industries Vs State of Haryana and others.

1. Please refer to this office memo no. 53/50/2015-5CI dated 20.3.2015 vide which the committee for formulation of Relocation Policy for shifting of Industrial Units operating from residential area was constituted. (copy enclosed for ready reference)
2. I, have been directed to inform that the Relocation Policy for shifting of Industrial units operating from residential areas has been notified vide notification no. 2/29/2016-R-II dated 20th July, 2016. The copy of the same is enclosed with request to take the necessary action on the points of the policy related to your Department and send the action taken report to this office as this case is listed for 4.10.2016 and the status report regarding implementation of this policy is to be submitted before the Hon'ble High Court.

D.A: As enclosed

(Sunil Verma)
Assistant Town Planner,
for Director Urban Local Bodies,
Haryana, Panchkula

Endst. No. DULB/CTP/TP/A2/2016/ 5541-71 dated: 04/8/16

A copy of the above is forwarded alongwith the copy of the notified policy to the following with request to carry out survey regarding number of Red,

Orange, Green and House Hold Units located within the residential and send the action taken on these industries/ unit as per the clause no. 8.5 of the policy.

- i. All the Commissioners of the Municipal Corporations of Haryana State
- ii. All the Deputy Commissioners in the State

(Sunil Verma)

Assistant Town Planner,
for Director Urban Local Bodies,
Haryana, Panchkula.

CC:

1. PS to CS, Haryana for kind information of Chief Secretary, Haryana
2. PS to PS, ULB for kind information of Principal Secretary to Govt. Haryana, Urban Local Bodies, Haryana, Chandigarh
3. PA to DULB for kind information of Director, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula

/ 897

**Haryana Government
Urban Local Bodies Department
Notification**

Dated : 20th, July, 2016

No. 2/29/2016-R-II, In exercise of the power conferred by Section 398 (2) (a) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and power conferred by Section 250 (a) of Haryana Municipal Act, 1973, the Governor of Haryana hereby directs for the information of general public the following Relocation Policy for shifting of Industries operating in the Residential Areas.

1. Introduction/Background:-

The formulation of the re-location policy has been necessitated consequent to orders of Hon'ble High Court in CWP No. 11226 of 2013 (O & M) titled as Progress Industries v/s State of Haryana and others. The court issued directions to the State for framing a policy for shifting the industrial units operating in the residential areas.

2. Operative part of the order of the High Court:-

The above mentioned Civil Writ Petition alongwith other CWP Nos. 13134 to 13140 of 2013 were listed together for hearing and disposed of by a common judgment titled as CWP No.11226 of 2013 (O&M) titled as Progress Industries Vs. State of Haryana and others on dated 9.07.2014. All the aforementioned 8 writ petitions preferred by the petitioner(s) originated due to the closure of the factories by the respondents (Joint Commissioner, Municipal Corporation, Ballabgarh and Faridabad) on the ground that they were running in notified residential area localities and such industrial activities could not be permitted in violation of the notified zoning/master plan.

In addition to above, there was another prayer with regard to framing of policy for shifting such units from the residential area. It was felt that it was dire need of the day not only in the interest of public at large, but also in the interest of the industrial units and in addition, this would avoid unnecessary litigation. It was, therefore, directed that the Government shall do the needful after giving due publicity and after hearing all concerned.

First part of the order of the court pertains to the shifting of the manufacturing units out of the residential areas in case not permitted under the Municipal Committee Act and units in contravention of the municipal laws. The Hon'ble High Court mandated that there should be a non-discriminatory treatment of the manufacturing units operating in the residential areas in the municipal limits. Therefore, the policy needs to apply uniformly in all such similarly situated cases.

The second part of the order of the Hon'ble High Court refers to the running of the dangerous and hazardous factories specifically the pollution causing units. For the purpose of making policy recommendations, both have been considered.

3. Constitution of Committee:-

In pursuance of order dated 24.02.2015, Sh. Depinder Singh Dhese, Chief Secretary, Haryana and Sh. S.N. Roy, Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department assured that they will make efforts to frame the policy for the entire State of Haryana and they will also direct the Pollution Control Board to identify the polluting industries and their categories. They assured the Hon'ble High Court that the requisite policy will be framed within four months. Affidavit filed by Sh. Roy in Court was taken on record.

Since framing of a State Level Policy for shifting of industries from the residential areas is a major policy decision, involving different departments, therefore Chief Secretary of Govt. Haryana approved the Constitution of the following committee, for formulating the policy:-

898

1.	Principal Secretary to Govt. Haryana, Industries Department	Chairman
2.	Principal Secretary to Govt. Haryana, Urban Local Bodies Dept.	Member
3.	Principal Secretary to Govt. Haryana, Environment Dept.	-do-
4.	Director General, Town and Country Planning Dept. Haryana	-do-
5.	Chief administrator, HUDA	-do-
6.	Managing Director, HSIIDC	-do-
7.	Director, Urban Local Bodies, Haryana	-do-
8.	Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad	-do-
9.	Commissioner, Municipal Corporation, Gurgaon	-do-

The committee was required to formulate the policy and notify the same before the next date of hearing, which was 15.07.2015.

The committee observed in its first meeting that a similar exercise of relocation of industrial units from the residential areas was implemented by the State of Delhi ensuing an order of the Hon'ble Supreme Court of India. The policy of Delhi, since it was approved by the highest court of India, was taken as the reference document for the preparation of the policy for Haryana State.

4. Relocation of Industry in Delhi:-

A similar exercise arising out of a Supreme Court Order was implemented in the capital city of Delhi, where appx. 1,29,000 units that employed nearly 14, 40,000 workers were identified for relocation from residential areas. The committee decided that it will be instructive and useful to study the case of Delhi in some detail and draw lessons from the same for the purpose of making policy recommendation in the instant case especially in view of the fact that the highest court of the country had seen and ratified the policy prescriptions in case of Delhi.

The Hon'ble Supreme Court, vide Judgment dated 7th May, 2004 delivered in the matter of closure/shifting of unauthorized industrial activities in Delhi in residential/non-conforming areas, had passed certain directions in Writ Petition (Civil) No. 4677 of 1985 titled "M.C. Mehta Vs. Union of India & Others" which inter-alia included :-

4.1 "All Industrial units that have come up in residential/non-conforming areas in Delhi on or after 1st August 1990 shall close down and stop operating as per the following schedule:-

- 4.1.1 Industrial units pertaining to extensive (Extensive Industries have been classified as 'F' Category, Extensive industries include Auto parts, castings, acid, chemicals, paint, varnish etc.) industries within a period of four month;
- 4.1.2 Industrial units pertaining to light and service industries within five months;
- 4.1.3 Impermissible household industries within six months and
- 4.1.4 6,000 industrial units on waiting list for allotment of industrial plots within 18 months.
- 4.1.5 House Hold units that have been classified as per the attached list may continue to operate from the residential areas".

In case of Delhi, 122 household industrial activities were allowed to operate in the residential areas after obtaining necessary licenses from the relevant authority.

5. Consultation Committee-Stake Holder Comments:-

In compliance of the court order a committee for the purpose of policy formulation was constituted and after due deliberations with various experts and stake holders has attempted to address the

899

issue. Keeping in view the spirit of the order of Hon'ble Court, the committee formed under the chairmanship of the Principal Secretary Industries met every 15 days and held extensive consultative sessions to formulate a rational and practically implementable policy. A total of seven meetings were held with various stake holders at Chandigarh and Delhi to consider diverse viewpoints regarding shifting and relocation of industry.

6. Representations of the Industrial Associations:-

Industries Association of Jagadhri had in the year 2000 and later in the year 2005 given representations to the Director Town and Country Planning to recognize the typical nature of industrial activity of the Jagadhri town. During the publishing of the draft development plans, the Department was urged to declare the town as an industrial town and identify / allocate larger geographic areas for the manufacturing units and declare certain industry occupied areas as industrial zones, as major industrial activity was prevalent in those areas and it was not possible to distinguish between residential and industrial activity areas, as both co-existed.

6.1 Deliberations with Jagadhri Metal Association:-

During the deliberations, the representative of industrial units, broadly agreed that industrial units falling under the red category should be closed or shifted from the residential area. The units falling under orange category should be allowed to continue subject to compliance of rules and procedures and stipulations of Haryana State, Water and Air Pollution Control Board as well as other authorities of the State Government. The units falling under the Green category should be exempted from shifting as per the court order. The industry representatives were of views that the residential area wherein industrial units have occupation of more than 70% physical/ geographic area, (eg: Faridabad has a number of such industries occupied areas) should be declared/considered as industrial zone in-situ.

7. Inter Departmental Consultations:-

Inter Departmental consultations were held with Departments of Labour, HUDA, Urban Local Bodies and Town & Country Planning Department and the comments thereof alongwith counter comments of Department of Industries are given at Annexure -A.

8. Policy Recommendations:-

The following norms shall be followed with regard relocation of Industrial units working in residential areas:-

- 8.1 Clusters of Industrial concentration in controlled area pockets delineated as "residential areas" in the development plans, having more than 70% plotted geographic area within the cluster under industrial activity/use would be considered for regularization on the basis of actual surveys after review of the development plans by following the due procedure prescribed under the Act.
- 8.2 The due process shall diligently be followed before reviewing the development Plan by inviting comments from the general public on the draft need to be followed strictly in such a situation before modifying and revising the development plan.
- 8.3 In case a decision is taken to modify the land use and the development plan, the necessary provision with respect to charging of fees, prescription of zoning etc. need to be mandated accordingly.
- 8.4 Some Departments i.e. ULB, T& CP, Labour and Haryana State Pollution Control Board have opposed the idea of regularization of industrial colonies operating from the residential area, a conscious view needs to be taken whether a larger public interest would be served by shifting such a large number of industrial units enmass or they be retained by modifying the development plan, especially the areas, where the current existing land use is determined

900

after conduct of actual survey on the ground (Ground Truthing exercise) and found to be predominantly industrial as mentioned above, although the area is earmarked as residential.

8.5 Categorization for the purposes of Relocation;

The following categorization for the purposes of relocation shall be for industrial units (for manufacturing industries) only.

- 8.5.1 Red category Industries-To be shifted with immediate effect by giving them six months time.
- 8.5.2 Orange category Industries-To be shifted with immediate effect as in case of red category, but if these units comply with Pollution Control Norms, then they may be given two years of time to shift to conforming areas.
- 8.5.3 Green category Industries-These units may continue to be dealt with as per the existing provisions and norms of the Pollution Control Department and other relevant approvals from the concerned authorities.
- 8.5.4 House Hold Units-Attached list of manufacturing activities can continue in residential areas provided they are not operating from HUDA sectors or other planned and approved residential colonies.
- 8.5.5 Only non-hazardous and non-noxious industries having clearance from Pollution Control Department shall be permitted to operate from the residential areas.

8.6 Facilitation for shifting of Industry to conforming Industrial Zones:-

The State Government shall facilitate shifting/relocation of Industrial units to the conforming areas. In case of short fall of the industrial zone space, additional zones shall be identified and notified by the Department of Town & Country Planning Department / Urban and Local Bodies as per their respective mandates, in consultation with the Dept of Industries. Accordingly existing/new Development Plans shall be marked on map and the designated industrial zones shall be earmarked as the new hub of manufacturing.

- 8.6.1 Keeping in view the demographics, the social & economic impact on the shifting of industry from the residential areas, a phased but time bound shifting is planned.
- 8.6.2 State shall identify and notify zones and areas for the industry.
- 8.6.3 State shall facilitate the Change of land use for the mass scale shifting and relocation of the industry to conforming zones. The new Haryana Enterprises Promotion Policy-2015 envisages 31 blocks as No CLU zones and 75 Blocks as Auto CLU zones for the purpose of establishing Industries. These provisions of the policy can be fruitfully utilized for the shifting units out of residential areas.
- 8.6.4 Modernization and technological up-gradation shall also be encouraged and incentivized.
- 8.6.5 Green and clean technology adoption as provisioned in the new Enterprises policy shall be incentivized.
- 8.6.6 Applicable norms with regard to pollution control shall be enforced.
- 8.6.7 Suitable incentives and other measures, for shifting and relocation of industrial units not conforming to the land use norms shall be provided as per the provisions of the new Enterprises Promotion Policy.

901

8.6.8 Tiny industries operating from the residential area that are non hazardous and cottage industries are meant to augment family incomes of the poor/lower middle class of society shall be identified and permitted to operate.

9. Future Plan and prescription:-

- 9.1 To take specific measures to encourage cluster based industrial infrastructure.
- 9.2. Pollution norms shall be strictly enforced in the residential areas. Zero tolerance shall be enforced for effluent air and noise pollution.
- 9.3 In order to prevent re-occurrences of such non conformance, geo referenced smart card linked to filing EM-2 shall be made a mandatory instrument for availing incentives. These cards shall be made by empanelled agencies on a chargeable basis on PPP mode. The recent introduction of UAM (Udyog Aadhar Memorandum) by Ministry of MSME can also be adopted for this purpose.

10. Implementation and Monitoring:-

Since, majority of units to be impacted by this policy are located within Municipal limits in different towns of the State, for effective implementation of the policy for relocation of the Industry already running in residential area of the District, a committee under the chairmanship of Commissioner, Municipal Corporation and where Municipal Corporation is not existing of Deputy Commissioner will be constituted with the following members:-

1.	Commissioner, Municipal Corporation/ Deputy Commissioner	Chairman
2.	District Town Planner of the concerned District	Member
3.	Estate Officer , HUDA of the concerned District	Member
4.	Estate Officer of HSIIDC of the concerned District.	Member
5.	Secretary, Municipal Committee of the concerned District	Member
6.	RO, Pollution Control Board of the concerned District.	Member
7.	Joint/Deputy Director/ DIC of the concerned District.	Member Secretary

- 10.1 A Monitoring mechanism shall be put in place to ensure that the re-location policy is implemented in the letter and spirit.

11. Revoking earlier permissions:-

All other permissions, licenses, consents for the purpose of the manufacturing/conducting business for the Red and Orange units shall stand revoked from the respective dates of end of the period mentioned in para 8.5.1 and 8.5.2 beginning from the date of notification of this policy.

12. House Hold Industry:-

The traditional house hold industry that has been operating from the residential areas of the old towns, within the MC limits shall be permitted to operate. The same shall however, not be applicable to HUDA and other planned and approved residential colonies as these are governed by their own Acts, Rules and Bylaws. A list of house hold Industries and showing the permissible activities and the negative list of Industries is enclosed herewith.

913

(Refinery) Notes:

- i) A public utility service involving any of the activities referred to above shall be permitted subject to environmental laws.
- ii) Further additions /alterations to the list of Prohibited Industries could be made if considered appropriate and in public interest by the State Government to do so.

Anil Kumar
Principal Secretary to Govt. Haryana
Urban Local Bodies Department

Endst No. 2/29/2016-R-II

Dated : 20th, July, 2016

DUB (busy)
20/7/16

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Chandigarh with the request that the above notification in English may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies to the said notification to this office for record.

- Sd.
Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Govt. Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated : 20th, July, 2016

CTP
Ard
20/7/16
ATD-IV

Endst No. 2/29/2016-R-II

A copy of the above mentioned notification is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No.11-14, Sector-4, Panchkula.
3. All Deputy Commissioners in Haryana State.
4. All Commissioner, Municipal Corporation, Haryana.
5. All Sub Divisional Officers (Civil), Haryana.
6. All President/E.O/Secretary, Municipal Council/Committee, Haryana.

2
25.7.2016
APP-IV

Please procure the
APP from AD.
Banc. related to
this case.

AZ

R. Singh
Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Govt. Haryana
Urban Local Bodies Department

to Controller Urban Local Bodies Haryana
20/7/2016-29040
21 JUL 2016